[Mr. Speaker]

(b) that he, misusing his official position, meddled with the affairs of independent Constitutional bodies as evidenced, among others, by his conduct in withdrawing from the files of the Election Commission a letter dated the 5th May, 1977, he had written in his capacity as the leader of the B.L.D.

This House hereby records its indignation against and disapproval of the conduct of the Home Minister."

The motion was negatived.

14.25 hours

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में यह आरोप लगाया गया मैंने घर मंत्री की राय से एक डाक्टर के साथ पक्षपात किया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये मौका दें। मैं कोई ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डा० जे० पी० सिंह के साथ पहले की मिनिस्ट्री ने ज्यादती की थी, और 1976 में ....

SHRI VAYADAR RAVI (Chirajukil): Sir, I am on a point of order. A Minister can make a statement only under Rule 372 and he should first write to the speaker. He cannot make a statement like this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is making a personal explanation.

SHRI VAYALAR RAVI: Has he got your permission to do so ? He should get prior permission.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना स्टेटमैंट बाद में दे दें।

14.27 hours

MOTION RE : CONTINUING PRICE RISE

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सदन के सामने अपना यह प्रस्ताव रखता हूं :

"That this House expresses its great concern over the continuing price rise in the country and urges upon the Government take urgent steps to check the price rise".

आज से चार महीने पहले भारत की जनता ने जनता पार्टी पर अपना विश्वास प्रकट किया था। उस समय हम ने, जनता पार्टी के लोगों ने, दो वायदे किये थे : एक तो यह कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता देंगे, और दूसरा यह कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ हम हर एक को खाने के लिए रोटी भी देंगे। हम ने इन चार महीनों में अपना पहला वायदा पूरी तरह से पूरा कर दिया है। आज हमारे देश में हर एक आदमी स्वतंत्र है, किसी प्रकार की कोई भी पाबन्दी नहीं है, प्रेस आजाद है, अदालतों पर कोई पाबन्दी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारे उधर के साथी भी इस बात को स्वीकार करेंगे।

दूसरा वायदा अभी हमें पूरा करना है। उस के लिए सरकार कदम उठा रही है। उसे पूरा करने में सब से बड़ी बाधा अगर कोई है, तो वह है कीमतों का बढ़ना, और अगर उसे न रोका गया, तो देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती है। अगर देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक रखना है, तो स्टेबिलिटी आफ प्राइसिज बहुत जरूरी है। इस लिए यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ने प्राइस राइज को नहीं रोका, तो शायद हम अपने दूसरे वायदे को पूरा नहीं कर पायेंगे।

यह सही है कि चीजों के दाम पिछले कई सालों से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद दाम बढ़े है। दाम पिछले साल भी बढ़े, उस से पहले साल भी बढ़े—कई सालों से दाम बढ़ रहे है। जो नीतियां पिछली सरकार ने अपनाई, उन्हीं का यह फल है कि आज दाम बढ़ रहे हैं। यह पिछली सरकार की एक लेगेसी है। लेकिन इस के बावजूद हमें कीमतों को स्थिर रखना पड़ेगा और हम ने जनता के साथ जो वायदे किये हैं, उन्हें पूरा करना पड़ेगा।

अगर दामों को बढ़ने से रोकना है तो सब से जरूरी यह है कि हमें कुछ फिस्कल डिसिप्लिन पैदा करना होगा। अभी सप्लाई बढ़ती

जा रही है । 1975-76 में करीब 10 परसेंट मनी सप्लाई बढ़ी और 76-77 में 19 परसेंट बढ़ी । 1975-76 में 1200 करोड़ रुपये की मनी सप्लाई हुई और 76-77 में 2400 करोड़ रुपयें की मनी सप्लाई हुई । उस के मुकाबिले में 75-76 में प्राइस राइज केवल 6 परसेंट थी और 76-77 में वह 12 परसेंट हो गई । अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस राइज ज्यादा होती है और मनी की सप्लाई कम होतीहै तो सप्लाई अगर ज्यादा भी बढ़ जाय तो भी प्राइस राइज उस हिसाब से रुक जाती है ।

अभी मार्च से जुलाई तक मनी सप्लाई पाच परसेंट ज्यादा बढ़ी है । जब से जनता पार्टी की हुकूमत आई है पांच परसेंट ज्यादा बढ़ी है और करीब करीब 4 परसेंट प्राइस ज्यादा बढ़ी है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों का अगर ठीक तरह से विश्लेषण किया जाय तो एक बात समने आएगी कि केवल कुछ चीजें ऐसी है जिन के दाम ज्यादा बढे है । बाकी चीजों के दाम इतने नहीं बढ़े हैं । जैसे तेल के दाम बहुत बढ़ गए और इसी प्रकार से और कुछ चीजों के दाम बढ़ गए हैं । अगर चीजों के दाम हमें कम करने और बढ़ने से रोकने हैं तो उस के लिए मनी सप्लाई के ऊपर कोई लिमिट लगानी चाहिए । आप यह तय कर लें कि इस से ज्यादा मनी सप्लाई इस साल के अंत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर भी नही होने देगें । पहले यूरप के देशों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दाम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हर देश ने प्रायः यह तय कर लिया है कि मनी की सप्लाई हम ज्यादा नहीं देंगे और उन्होंने कुछ सीमा बांध दी है ।

मुझे मालूम नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगे या फूड मिनिस्टर जवाब देंगें लेकिन मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात की सीमा तय कर लें कि इस साल के अंत में मनी सप्लाई को इस से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जायगा । आप को मालूम है कि पांच सौ करोड़ के ओवर-ड्राफ्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंटस ने लिए हैं । अब मेरा सुझाव यह है कि आप स्टेट गवर्नमेंटस से कहें कि जो ओवर-ड्राफ्ट हैं उस को क्लीअर करें । उस के लिए या सेंट्रल गवर्नमेन्ट से लें या अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं । उन के जो एरियार्स हैं वे वसूल होने चाहिए । किसी प्रकार से भी ओवर-ड्राफ्ट खत्म होना चाहिए । मैं तो यह भी सुझाव दूगां कि रिजर्व बैंक को यह आदेश दीजिए कि वह इस चीज को इम्प्लीमेंट करें कि यह हमारी सीमा है, इस के बाहर किसी को नही जाना चाहिये । कोई स्टेट गवर्नमेंट ओवर ड्राफ्ट के लिए जाती है तो उन को बता देना चाहिए कि हम ओवर ड्राफ्ट के हक मेंनहीं हैं । इसी तरह से कामर्शियल बैंक्स के ओवर ड्राफ्ट हैं । यह सब काम अच्छा हो कि रिजर्व बैंक को दे दें ।

तो पहला तो मेरा सुझाव यह है कि अगर दाम कम होने हैं या बढ़ने से रोकने हैं तो कुछ फिस्कल डिसिप्लिन होनी चाहिए । मनी सप्लाई पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए । जब तक वह कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता ।

दूसरा मेरा कहना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में । उस के अंदर मंत्री महोदय ने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ घोषणा भी की है । सरकार ने दस बारह चीजें बताई हैं ।

Decision to reduce expenditure and avoid all forms of ostentation.

Decision to release more cereals through the public distribution system.

More liberal allocation of rice to meet the requirements of the public distribution system in the deficit States.

Increased release of non-levy sugar for the months of May and June.

Removal of restrictions of inter-State movement of wheat.

Imposition of an export duty of Rs. 5 on tea.

Regulating exports of potatoes and onion.

Staggering to the extent possible exports of cement.

[श्री कंवर लाल गुप्त]

इस तरह के उन्होंने और भी कई कदम उठाये हैं। यह कदम बिल्कुल ठीक हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं जिन कदमों की उन्होंने घोषणा की है अगर उनको ठीक तरह से इम्पलीमेंट करवें तो कुछ न कुछ सहारा हो सकता है और दाम तेजी से बढ़ने से रुक सकते हैं। लेकिन मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केवल यह बात कहने से कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, उसका तो एक ही मतलब है कि हम और हमारी सरकार दामों के बढ़ने से चिंतित है लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने चार महीनों में क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए? दाम बढ़ रहे हैं, यह कोई नयी चीज नही है। आपको पहले मालूम था, जिस दिन आपने मंत्रिपद की शपथ ली थी तभी आपको मालूम था कि दाम बढ़ रहे हैं। तो इन चार महीनों में आपने क्या कदम उठाये, यह मैं जानना चाहता हूं। मेरा कहना है कि इस तरह से एक दिन बीत गया, हफ्ते और महीने बीत गए लेकिन उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता गया जैसे कि पहले चलता था। तो इस तरह से काम नही बनेगा। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता तो पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप कीजिए और जो इस तरह के आफिसर्स हैं जो काम नहीं करते हैं उनको अलग कीजिए। चार महीने बीतने के बाद भी, जो आशा जनता पार्टी से आर्थिक मामलों में की जाती थी, यह आशा जनता पार्टी ने पूरी नही की। आज लोग हम से पूछ रहे हैं कि आशा पूरी क्यों नहीं की। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बारे में आप विचार करें और देखें कि चार महीनों में वह कदम क्यों नही उठाये गये?

पहली बात जैसी मैं ने कही, यह बात अच्छी है कि केवल दालों में प्राइसेज ज्यादा बढ़ी हैं, राकाटन में बढ़ी है, काटन टेक्सटाइल में बढ़ी हैं, और आयल सीडस् में बढ़ी हैं। अगर इन चार चीजों को आप छोड़ दीजिए तो बाकी चीजों में जो इंक्रीज है वह बहुत थोड़ी है। आयल सीड्स की होलसेल प्राइस 1957 से 1977 तक 84 प्रतिशत इंक्रीज हुआ हैं। रा-काटन में 48.3 परसेंट की इंक्रीज हुई है। पलसेज में 14.1 परसेट की इक्रीज हुई हैं और काटन टेक्सटाइल में 17.2 परसेंट की इंक्रीज हुई है। मार्च, 1977 से मई, 1977– इन तीन महीनों में सारी होलसेल प्राइसेज में केवल ढाई परसेंट की इंक्रीज हुई है जो अब शायद साढ़े तीन परसेंट हो गई होगी। अगर आप इन तीन चार चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, इनकी प्राइसेज को कंट्रोल कर लेते है तो सारे ढाचे को आप कंट्रोल कर लेंगे।

जहां तक दालों का सवाल है, इसका एक कारण तो यह हैकि पिछले कई सालों से दालों की पैदावार 11 मिलियन टन के करीब हो रही है। इस से ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इसी तरह से ग्राउंड नट आयल का प्रोडक्शन 1975–76 में 16.2 लाख टन था जो 1976–77 में चार पांच लाख टन कम हो गया।

तो प्राइस राइज का एक कारण यह है कि पैदावार कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए कुछ बातें अच्छी भी हैं। एक तो यह कि हमारे पास फारेन एक्सचेंज का रिजर्व काफी हैं और दूसरी अच्छी बात यह है कि हमारे पास अनाज का बहुत बडा बफर स्टाक है। करीब 21 मिलियन टन अनाज हमारे पास है और इस साल के बजट में हमने 800 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट करने के लिए प्राविजन किया है। यह दोनों बातें होने के बाद मैं समझता हूं सरकार को इस पोजीशन में होना चाहिए कि वह इन तीन चार चीजों के दामों को बांध ले। अगर इन तीन चार चीजों के दाम बांध लिए तो हम कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में हम लोगों को सुविधा दे सकेंगे। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि सरकार को सीलिंग लगानी चाहिए, सीलिंग आन प्राफिट–इण्डस्ट्री पर, होलसेलर्स पर और रिटेलर्स पर। क्योंकि इन तीनों आर्गेनिजेशन्ज पर पूरा डिस्प्लिन होना चाहिए। जब तक ये तीन डिस्प्लिन्ड नहीं होंगी, तब तक स मूल्य बढ़ते

रहेंगे। इण्डस्ट्रीज ने श्री मोरारजी भाई को विश्वास दिलाया है कि उन्होंने प्राइसेज को फ्रीज कर दिया है, लेकिन मेरे पास 25-30 आइटम्ज के आकडे है-जिस म कमोडिटी का नाम है, मार्च मे जो प्राइस थी वह दी गई है और 1-8-1977 को क्या दाम थ, वे दिये गये है। मैन्यूफैक्चरर्स का नाम भी दिया है और कितने दाम बढे है, इसकी तफसील भी दी गई है। आप देखिये-रा-मैटीरियल, इन्पुट्स के दाम नही बढ़े है, फिर भी इण्डस्ट्रीज ने 10 से 20 परसेन्ट तक दाम बढ़ा दिये हैं। मैं जानना चाहता हू-हमारी सरकार क्या कर रही है? आप उनसे पूछते क्यो नही, कि उन्होने दाम क्यो बढ़ाये है? आप के डिपार्टमेन्ट मे एक सेल होना चाहिए, जो इस बात की घोषणा करे कि अगर कोई इण्डस्ट्री दाम बढाती है, तो उसको पहले आप को खबर करनी चाहिये, उसे जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि उसने दाम क्यो बढ़ाये है।

मैं आप की आज्ञा से कुछ आकडे बताना चाहता हू-सर्फ के दाम 16 परसेट ज्यादा कर दिये गये, विम के दाम 10 परसेट ज्यादा किए गये। मस्टर्ड आयल का दाम बढा है। कागज का दाम देखिये-जो एमर-मेल का कागज है, उस का दाम एक हजार रुपये टन ज्यादा हो गया-तीन महीने के अन्दर। दूसरे कागज के दाम भी बढे है, जिन की फिगर्स मेरे पास है। कैलशियम कार्बाइड का दाम दस परसेट बढ गया। वायर का दाम 800 रुपया प्रति टन बढ गया। कपडे का दाम देखिये-जो गरीब आदमियो का कपडा है, जैसे मलेशिया-नैपोलिन जो पहले 1 रुपये 95 पैसे मीटर था, अब उस का दाम पौने तीन रुपए मीटर हो गया यानी 20 परसेट बढा दिया गया। मलेशिया कैप्तन जो पहले 1 रुपये 80 पैसे मे बिकता था, अब 2 रुपये 21 पैसे हो गया, यानी 18 परसेंट बढ गया। ट्विल का दाम 28 परसेट बढ गया। मैं पूछना चाहता हू-क्या आप ने इन को दाम बढाने की इजाजत दी है और अगर आप ने इजाजत नही दी है, तो आप देखिये कि 20 मार्च को जब चुनावो के नतीजे निकले थे, तब से आज तक इतने कैसे दाम बढे, इसका क्या जस्टिफिकेशन है, इस का एक्सप्लेनेशन हमारी सरकार को उन से मागना चाहिये। मै चाहता हू कि मत्री महोदय इस की जाच कराये कि दाम पिछले दिनो मे इतने क्यो बढे और इस का जस्टिफिकेशन क्या है।

कुछ ऐसी इण्डस्ट्रीज भी हैं जिन में पहले ही बहुत प्राफिट होता है। टैरिलीन मे 60-70 परसेन्ट प्राफिट होता है। मैं चाहता हू ऐसी हर चीज के बारे मे जाच होनी चाहिये और इसीलिये मैंने आप के सामने सीलिंग-आफ प्राफिट की बात रखी है।

दु ख की बात यह भी है कि हमारे जो ब्यरोक्रेट्स है-किसी को दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, किसी को ढाई हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। जो बडे-बडे इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स हैं, उन का पब्लिक रिलेशन्ज डिपार्टमेट होता है, वे लोग इन के साथ अपना सम्बन्ध घनिष्ट बना लेते हैं, ये लोग उन की कास्ट पार्टीज मे जाते हैं और जब उन लोगो से जस्टिफिकेशन मागा जाता है, तो जो जस्टिफिकेशन वे देते है, उस को एम्बू करके फाइल मे लगा देते हैं। मैं चाहता हू कि आप अपने अफसरो की भी कसाई कीजिये। जो इस तरह के लोग हैं, जो इण्डस्ट्रीयलिस्टस के साथ मिलकर जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, उस को खत्म करना चाहते हैं, उन का हिसाब-किताब करना चाहिये। जनता पार्टी की आइडेन्टिफिकेशन साधारण आदमी के साथ पूरी तरह से है, हमारा उन के साथ कमिटमेट है, हम उस से पीछे नही हटेंगे, इस लिये सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि जो अफसर इस तरह के कामो मे बाधा डालते है, इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स के हाथो मे खेलते है-एसे अफसरो को यहा नही रखना चाहिये। सरकार देखे कि इण्डस्ट्रीज के लोग कितना प्राफिट कमाते हैं और उन्होने कितने

[श्री कंवर लाल गुप्त]

दाम बढ़ाये हैं तथा दाम बढ़ाने का जस्टिफिकेशन क्या है।

इसी तरह से मैं होल-सैलर्स और ट्रेडर्स के बारे में कहना चाहता हूं। सारे होल-सैलर्स खराब नहीं हैं, लेकिन कुछ जरूर गड़बड़ करते हैं। जैसे सब्जी, फल पैदा होता है, मंडी में आता है, उस को उठा कर कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और जैसे-जैसे दाम बढ़ते जाते हैं उस को वहां से निकालते जाते हैं। मैं चाहता हूं कि होल-सैलर्स के प्राफिट का भी सीलिंग होना चाहिये।

इसी तरह से रिटेलर्स की समस्या है, जो 25–30 परसेंट प्राफिट लेते हैं। इन सब चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए तभी जा कर दाम ठीक रह सकते हैं अन्यथा अगर इन चीजों को अनुशासित नहीं किया गया, तो दाम बढ़ते जायेंगे और जो चीज हम करना चाहते हैं वह पूरी नहीं होगी।

इसलिए मैं एक सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहता हूं कि आप की जो एकोनोमिक मिनिस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज की, फाइनेन्स की, एग्रीकल्चर की और भी कोई एकाध मिनिस्ट्री होगी, उन सब का ठीक कोआर्डीनेशन कीजिए और जब तक वह कोआर्डीनेशन ठीक नहीं होगा, आप मूल्यों को बांध नहीं सकते और उस के लिए सजशन यह है कि आप एक कमेटी बनाइए जिस में चारों मिनिस्ट्रियां शामिल हों, एक्सपर्टस हों और सदन के मेम्बर हों, जो डे-टू-डे वाच रखे कि दाम ठीक जा रहे हैं या नहीं और जिस के पास रिपोर्ट आनी चाहिए कि इंडस्ट्री ने दाम क्यों बढ़ाए हैं, होलसैलर्स ने दाम क्यों बढ़ाए है। यह कमेटी एक वाचडोग की तरह से रहेगी और उस कमेटी में रेड-टैपइज्म नहीं चलना चाहिए और उस कमेटी को अधिकार भी दिया जाना चाहिए। आप ने एक्सपोर्ट कुछ चीजों का बन्द कर दिया और उस से फायदा भी हुआ लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा करने में इतनी देर क्यों लग गई, 4 महीने क्यों लग गये। इम्पोर्ट करने का भी उस कमेटी को अधिकार होना चाहिए। इस समय धारिया साहब यहां पर नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि हम व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे लेकिन आप ने आज तक क्या कार्यवाही की है।

यह जो तेल के इम्पोर्ट के लाइसेंस दिये गये थे, तो क्या मैं आप के जरिये से अपनी सरकार से पूछ सकता हूं कि उस में जिन व्यापारियों ने बंगलिंग की, जिसका वजह से आज भी तेल नहीं मिल रहा है, उन को आप ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मेरा एक प्वाइंटेड क्वेश्चन आपसे यह है कि आप के पास रिपोर्ट है कि किन किन लोगों ने बंगलिंग किया है तो उन को आप ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। आप कहते हैं कि हम इन्क्वायरी करा रहे हैं। आप इन्क्वायरी कराते हैं तो छः, आठ महीने उस में लग जाते हैं। इस पर आप कमीशन बैठाएंगे तो साल भर तक इन्क्वायरी होती रहेगी और कोई कार्यवाही उन के खिलाफ नहीं होगी। इस तरह की लेथार्जी, इस तरह का रेड-टैपइज्म अगर यह सरकार करती रहेगी, तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप दामों को बांध नहीं सकते हैं और जो वायदे आप ने किये हैं वे पूरे नहीं होंगे। मैं यह मानता हूं उपाध्यक्ष जी, कि हर ट्रेडर खराब नहीं होता है। ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी और मैं यह भी जानता हूं कि जेब हम लोग जल में थे और पूरी तरह अन्धकार था और अगर कोई आदमी जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट में जरा भी मदद करता था, तो उस को पकड़ कर अन्दर कर दिया जाता था और जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेना पाप था, उस समय इन लोगों ने हमारी मदद की थी। मुझे याद है कि मेरी कांस्टीटुयेंसी में एक आदमी सुबह नहा रहा था, नल के नीचे और जब उस गरीब आदमी ने कहा 'जय नारायण, जयनारायण', तो वहां से उसी समय पुलिस की लारी निकली और उन्होंने समझा कि यह आदमी जयप्रकाश नारायण के नारे लगा रहा है, तो उस को पकड़ कर उन्होंने हमारे साथ बन्द कर दिया।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): It is an old joke.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: It is not an old joke. I can produce that man.

उपाध्यक्ष जी, जब ऐसा मौका था, तो उस समय भी काफी व्यापारी ऐसे थे, जिन्होंने हमें धन दिया और हमारे परिवार के लोगों की सहायता की लेकिन इस का यह मतलब नहीं है कि जो व्यापारी है, उन को एक्सप्लायट करने का हक होगा । हम हर एक व्यापारी को कन्डेम नहीं करते । जो व्यापारी ईमानदार हैं सरकार को उन को एन्करेज करना चाहिए, उन की मदद करनी चाहिए, लेकिन जो बईमान हैं, उन को सरकार को सख्त दंड देना चाहिए और जब तक उन को दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती । मेरा कहना यह है कि जो तेल का इम्पोर्ट करने वाले व्यापारी थे और जिन्होंने जानबूझ कर प्रोफिटियरिंग के लिए इम्पोर्ट नहीं किया, उन को गिरफ्तार करना चाहिए, तुरन्त गिरफ्तार करना चाहिए । हमारी मशीनरी तेज नहीं चलती, आहिस्ता आहिस्ता चलती है । देखने वाली चीज यह है कि कब किया जाता है । अगर इस में एक साल लगा दिया गया तो मेरा विश्वास है कि जनता पार्टी के ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाएगा । अगर हम ने इसको उससे पहले हल कर लिया तो यह एक बड़ी सफलता होगी । मैं नहीं कहता हूं कि तुरन्त यह काम हो सकता है । हथेली पर सरसों नहीं उग सकती है । समय तो लगेगा लेकिन चार छः महीने के बाद दाम गिर रहे है इस प्रकार की स्थिति देश में जरूर लानी चाहिये । जहां तक शार्टटर्म मैशर्ज का सम्बन्ध है, आप इंडस्ट्री, होलसैलर रिटेलर को डिसिप्लिन करिये । एक कमेटी बनाइये । वहां पर रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिये । उसको काफी अधिकार दिए जाने चाहियें । ऐसा किया गया तब तो कुछ हो सकता है वर्ना नहीं ।

इसके साथ साथ लांग टर्म मैशर्ज भी आपको लेने होंगे । पैदावार जो कम हुई है उसको आपको बढ़ाना चाहिये । अभी तक सरकार का कंस्ट्रेशन गेहूं और चावल पर रहा है । उसके नए नए सीड निकाले गए हैं । ऐसा लगता है कि किसान के लिए यह ज्यादा फायदेमन्द है कि वह गेहूं बोएं । दालों, काटन आदि की तरफ पहली सरकार ने ध्यान नहीं दिया है । मेरी आप से प्रार्थना है कि इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये और इनके नए नए सीड निकाले जाने चाहियें । यह भी बहुत जरूरी है कि फार्मर्ज को ठीक दाम मिलें । तभी वह उस चीज को बोएगा । इसके लिए एक काम आप यह भी कर सकते हैं कि उसको इनपुटस सस्ते दिलाएं, उनको सरकार सबसिडी दे । अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे कि अगले एक साल के अन्दर इन चीजों की दिक्कत नहीं रह जायेगी । मुझे याद है और मैंने सुना है कि बिहार में जहां दाले होती थी पैदा वहां पर चालीस हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । ये जो चीजें हैं इनकी तरफ आपका तुरन्त ध्यान जाना चाहिये ।

मौनोपौली चाहे वह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल पर हो, होलसेल लेवल पर हो या रिटेल लेवल पर हो उसको खत्म किया जाना चाहिये । गवर्नमेंट को बीच में आ जाना चाहिये । जैसे मैंने कहा सब्जियां हैं, फूटस हैं उनको होलसेलर खरीदते हैं और कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं । जो प्रोडयूस करता है उसको वाजिब दाम नहीं मिलते हैं । मेरा सुझाव यह है कि जैसे दिल्ली के चारों तरफ जहां जहां भी सड़कें मिलती है, वहां पर सरकार को बड़ी बड़ी मार्किटस बना देनी चाहिये और वहां पर दूकानें एलाट सरकार करे और चाहे तो उन मार्किटस को कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे कर इस काम को करवाए । अभी तक क्या हो रहा है। फलों के मौसम में अगर संतरे का मौसम है तो सन्तरा लोगों को खाने को नहीं मिलता है और यह इसलिए होता है कि सारा संतरा कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है । कुछ समय के लिए तो लोगों को मौसमी

[श्री कंवर लाल गुप्त]

फल मिलने चाहिये । इस प्रकार से अगर सरकार व्यवस्था करेगी तो चीजों के दामों को कुछ हद तक रोका जा सकता है ।

मैं सिमेंट की बात करता हूं । जितना सीमेंट का उत्पादन होता है उसका आधा तीन चार फर्में बनाती हैं । उनकी सांठगांठ भी है । उसकी एसोसिएशन भी है । और उसका नतीजा यह है कि मनमाने दाम तय करते हैं । डीलर्स भी उन्हीं के हैं । मेरा सरकार को सुझाव है कि इंडस्ट्री को आप कहिये कि उनके डीलर अलग होने चाहिये और इंडस्ट्री के मालिक अलग होने चाहियें । उनके इम्प्लाईज में नहीं होने चाहिये । अगर कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग होती है या दाम बढ़ते हैं तो आप इंडस्ट्री के मालिक को पकड़िये और उनको जिम्मेदार ठहराइये । जो डिस्ट्रिब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं उनको उनसे अलग कर दीजिये, दूसरे लोग होने चाहिये ताकि उनको जिम्मेवार ठहराया जा सके । अभी तीन, चार आदमी माल पैदा करते हैं और डिस्ट्रीबयूटर्स भी इन्हीं के लोग हैं और दोनों मिल जुल कर पैसा खाते हैं । इसको रोकना चाहिये और यह मोनोपोली खत्म होनी चाहिये ।

कपड़े के अन्दर पिछली सरकार ने स्टैन्डर्ड क्लौथ का प्रोडक्शन कम कर दिया है । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे और स्टैन्डर्ड क्लौथ की जितनी आवश्यकता है यह ऐश्योर कराना चाहिये भारत की जनता को कि जितना गरीब आदमी का कपड़ा है वह सरकार ठीक दाम पर लोगो को देगी । एक चीज इसके रास्ते में बाधा है, मैं जानता हूं देश में बिजली की कमी है, हड़तालें भी हो रही है, तरह तरह की मांगें भी हो रही हैं और उससे चीजो की पैदावार रूक गई है, काफी कम हो गई है । मैं देखता हूं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आहिस्ता-2 कम होती जा रही है । यह सवाल कोई एक पार्टी का सवाल नही है बल्कि सारे देश का सवाल है, सारे सदन का सवाल है और इसको पोलिटिकल दृष्टिकोण से नही देखना चाहिये । मैं अपने सभी तरफ के साथियों से कहना चाहता हूं कि क्या सारी पोलिटिकल पार्टीज बैठ कर के इस तरह का निश्चय नहीं कर सकती कि दो साल तक कोई हड़ताल नही होगी और जो लेबरर्स के ग्रीवांसेंज है उसके लिये सरकार कोई रास्ता निकाले ताकि उनको भी तकलीफ न हो और देश का प्रोडक्शन भी कम न हो । अगर ऐसा नही होगा तो देश का प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ सकता । दो साल के लिय बंदिश लगानी चाहिये । लेकिन इसके माने यह नही है कि लेबरर्स की उचित मांगों का गला घोट दें । उसके लिये सरकार को कोई मशीनरी बनानी चाहिये । लेकिन सब पार्टीज इसमें मिल कर एक नेशनल कान्सेंसस डेवलप करें ।

एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं । फूड कारपोरेशन के पास करीब 21 मिलियन टन अनाज है और इसमें करीब 2,190 करोड़ रु० का इन्वेस्टमेन्ट है मार्च 1977 में और हर साल करीब 400 से लेकर 500 करोड़ रु० सरकार सबसिडी देती है । यह अच्छी बात है कि हमारे पास बफर स्टाक है और दो साल तक लोगों को अनाज दे सकते हैं । लेकिन मुझे यह लगता हैं कि इसमें जरूरत से ज्यादा पैसा ब्लाक हुआ है । अगर सरकार 21 मिलियन टन के बजाय 15 मिलियन टन का बफर स्टाक करे और बाकी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बेच दे तो जो पैसा बचेगा उससे तेल, काटन और कपड़े का बफर स्टाक बनायें । तो इतने ही पैसे के अंदर हम चार, पांच चीजें जनता को ठीक दामों पर दे सकते है । लेकिन यह सारा आपने ब्लाक किया हुआ है यह ठीक नही है ।

15.00 hrs.

एक कारण इसका और भी है, एक चीज के बारे में मै मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हू । दालो के दाम जो बढ़ रहे हैं उसका एक कारण यह भी है कि स्मगलिंग दालों का बढ़ रहा है । नेपाल में हो रहा है, खाद्य मंत्री

जी इसको स्वीकार करेंगे, और सरकार की मशीनरी जितनी इफेक्टिव होनी चाहिये उतनी नहीं है। दालें बांगला देश, नेपाल, चीन, बर्मा में जा रहीं हैं। सब बाउन्ड्रीज पर हमारे अफसर स्मगलस से मिले हुए हैं, इसको रोका जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, मैं इसके पक्ष में नही हूं कि किसी को पकड़ने के लिये मीसा लगाया जाये। जनता पार्टी इस बात मे कमिटेड है कि बगैर मुकदमा चलाये किसी को अंदर नहीं करेगी। लेकिन मैं यह मांग करता हूं कि एसेन्शियल कमाडिटीज एक्ट को थोड़ा तेज किया जाये, उसमें ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहियें। जो बेईमानी करता है, उस को पकड़कर अंदर किया जाना चाहिये और जब तक कोर्ट में केस फाइल न हो, तब तक उस की जमानत नहीं होनी चाहिये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि बिना मतलब इसके अंदर लोगों को पकड़ लें। पहले की सरकार पहले से ही बता देती थी कि 50 आदमी पकड़कर लाने हैं, उनका कसूर हो या न हो। जनता पार्टी की यह नीति नहीं है, न हो सकती है और हमारे मंत्री महोदय करेंगे भी नहीं। जो दोषी नही हैं, उनको पकड़ना ठीक नही है, लेकिन जो दोषी हैं उनको पकड़ने का अधिकार होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का यह सत्र एक दो दिन में खत्म हो जायेगा, मै मांग करूंगा कि आर्डिनेन्स के जरिये से एसेन्शियल कमोडिटीज् एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिये और जो बेईमानी करे, उसको पकड़कर अंदर करने का अधिकार होना चाहिये।

डीमोनिटाइजेशन की बात भी कही जाती है। मेरे ख्याल से जो शार्ट-टर्म मेजर्स और लांग-टर्म मेजर्स सुझाये गये है, अगर वह पूरे कर लिये जायें तो डीमोनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है। मैं यह देख रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ब्लैक-मार्केटिंग फिर शुरु हो गई है और बढ़ती जा रही है। एमरजेंसी में कुछ कम हो गई थी, लेकिन अब आहिस्ते-आहिस्ते बढनी जा रही है। हमारे मंत्री महोदय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिसमे ब्लैक-मार्केटिंग न हो। इसमें चाहे कितने भी बड़े से बडे लोग हों, उनको छोड़ा नही जाना चाहिये। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी सरकार का रास्ता, नीति और एनेलिसिस ठीक हैं। केवल जरूरत इस चीज की है कि रेड-टेपिज्म खत्म हो जाये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): उपाध्यक्ष जी, यह कह रहे हैं कि जो भी कानून है, उसका इफैक्टिवली इम्पलीमेंटेशन होना चाहिये, मगर पुलिस वालों में बहुत भय पैदा हो गया है कि हम लोग कुछ कार्यवाही करेंगे तो हम पर मुकदमा चल जायेगा और कमीशन बैठ जायेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त: जैसे कांग्रेस पार्टी ने पुलिस को छूट दे दी थी कि चाहे किसी को भी पकड़कर अंदर बंद कर दो, यह जनता पार्टी नहीं कर सकती। जनता पार्टी पुलिस को यह अधिकार नहीं देना चाहती कि वह किसी को भी पकड़कर ले जाये, लेकिन जो दोषी होगा, हम पुलिस को कहेंगे कि उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिये और निर्दोष को पकड़ना नहीं चाहिये। यह हमारी पालिसी है।

मै कह रहा था कि हमारी सरकार का एनेलिसिस ठीक है, जो कदम सरकार उठा रही है वह भी ठीक है लेकिन रेड-टेपिज्म जरूर है। इम्पलीमेंटेशन के लिये एफीशियेंट मशीनरी होनी चाहिये और यह हमारे लिये बहुत बड़ा चेलेन्ज है हमारी जनता पार्टी और सरकार के लिये। मैं आशा करता हूं कि हमारी पार्टी इस चेलेन्ज को स्वीकार करेगी। हमने एक वादा आजादी का तो पूरा कर दिया और वह दिन भी दूर नही होगा जब हम लोगों को कह सकेंगे कि हमारे देश में एक भी भूखा नही है, हरेक को रोटी

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मिलती है । इसलिये यह जरूरी है कि जो दाम आज बढ़ रहे हैं, उनको रोका जाये जिससे अर्थव्यवस्था ठीक हो, पैदावार बढ़े और शार्ट-टर्म पालिसी हमारी ठीक चले । मुझे विश्वास है हमारी सरकार इस पर जरूर अमल करेगी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Time has to be regulated; otherwise the purpose of the debate will be lost.

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): May I make a submission? I am one of the co-movers of this resolution. Should I be the unfortunate person to suffer on account of limitation of time?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Yuvraj to move the amendment.

श्री युवराज (कटिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह **जोड़ा** जाये ।

"ताकि जन साधारण को कुछ राहत मिले"

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will allow only ten minutes for every speaker. At 4.30 we have to begin non-official business.

AN HON. MEMBER: Then we will continue this tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Tomorrow there is already a subject which has been allotted.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: How can we finish within two hours? We have to start another motion at 4.30. We cannot finish it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: At least some speakers should get their turns today. Mr. Narsimha Reddy.

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad): Mr. Deputy Speaker, I would first congratulate Mr. Kanwar Lal Gupta for bringing this important resolution before this House. The most important burning problem of our country today is the rising prices. The prices of most of the essential commodities, since the last four months, are going up day by day, although there are some commodities where the prices are stable. As per the press statement, the rise in the wholesale prices is of the order of 4.5%. If the Government does not take any step to check this, I am afraid, that in another six to seven months, the prices will go to such an extent, where the percentage of people below poverty line, which is now about 40%, will go to 60 or 70 per cent.

I would congratulate Mr. Gupta who has already given some suggestions. One of the most important steps that the Government has taken is stopping the exports. I personally feel that this step, which the Government has taken as a temporary relief, would, in future become a big disease. Take for example, sugar. Sugar export has been minimised, almost banned. Today, the stocks of sugar in the factories are 23.60 lakh tonnes. In the corresponding period last year we had about 16.7 lakh tonnes. You can see a gap of seven *lakh* tonnes. Now, the sugar factories have incurred a loss of about Rs. 50 crores. If you stop exports, then automatically, the prices of the commodities would naturally come down for a short period. But what will be its effect? The ultimate effect would be on the poor agriculturist. In case of sugar, the effect would be, I can tell the House, that in future sugar growing seasons, the people will try to switch over to some other crop whichever fetches them a higher price. I would like to tell the hon. Minister that the step which this Government has taken *viz.*, stopping the exports is a dangerous step to this nation because, since the last thirty years, whether my friends agree or not, we have increased the production of all essential commodities in this country. We have started exporting also. Once you stop exports, automatically production will come down. So, I plead on behalf of the farmers that in the interests of the agriculturists and national production, this policy of stopping exports should not be adopted in future, because it has only a temporary effect for a short period.

Another step which the government propose to take is to use MISA against merchants. Do you think merchants are the only persons responsible for price rise? I do not think so. There may be some black sheep which I do not deny, but if you use MISA, I am afraid the prices will increase and not decrease, because the police will go to arrest the merchants with this weapon of MISA and demand any amount of money from them. It will lead to more corruption. No merchant pays money to the police from his pocket. Naturally this will be added to the price of the commodity and passed on to the consumer. Therefore, I request the government not to use MISA for arresting price rise.

The main reason for price rise is inflation. A lot of money has been brought into *circulation and because of inflation, prices* are going up. So, to check price rise, it

is necessary to check inflation. Secondly, credit facilities are given by the banks to merchants to store foodgrains. This enables the merchants to hoard the foodgrains and automatically prices go up. The Finance Minister is here and I request him to see that credit facilities for storing foodgrains are reduced. Thirdly, there is the speculation method adopted in this country. Without exchanging the commodity, one merchant purchases from another on telephone so many tons of foodgrains at a particular price. This speculation which goes on from one merchant to another without exchanging the commodity increases the price. Therefore, the government must check this kind of speculation.

Shri Kanwar Lal Gupta has also pleaded that there must be a limit to the price. I support his view. A ceiling on prices is necessary. First, the government should impose a ceiling on the price charged by FCI itself. Now there is a difference of Rs. 10 to Rs. 20 per quintal between the price at which FCI procures foodgrains and the price at which it sells it. The biggest white elephant is FCI and this is one main reason for price rise. We have a lot of buffer stock now. In the rainy season, the foodgrains stocked under tarpaulin get damaged to a great extent. The Minister of Agriculture himself has referred to the damage of paddy, rice and wheat stored under tarpaulins. This damage is increasing day by day. Whatever damages FCI suffers, it makes it up by dividing it amongst the commodities available with it at that time. Therefore, ultimately again the prices go up. So, I would plead with the Government to immediately take action on the foodgrains which are now lying under tarpaulin and stored for the last two or three years. There are some godowns, even the pucca godowns. If you open the shutter, you cannot go in. They are full of insects. You can imagine what damage is taking place. For the last two years there has been a lot of deterioration in the foodgrains which are stored and this is also one of the main reasons of price rise because they are the biggest bufferstocks of about 20 million tonnes. Therefore, I would request the Government to take necessary steps in this matter also.

Lastly, I would say that the steps which they are thinking are opening of fair price shops or mini super bazars everywhere. There are already so many fair price shops. I would request the hon. Minister to utilise them in the proper way and immediately supply to them all the essential commodities by fixing a price in such way that it should be somewhere between the producers' price and *the consumers'* price. The Government should not allow any fluctuation in price beyond that. By this, the producer will be satisfied and the consumer also will be satisfied. Now what is happening is this. Whenever the price falls, who suffers? It is the agriculturist who suffers. Whenever it falls, the agriculturist suffers, whenever it rises, it is the consumer who suffers. In between the Government and the producer, it is not the middlemen who suffer, but ultimately it is the producer and the consumer who are suffering. Therefore, I would request the hon. Minister to fix up a different price that should be the ceiling price.

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, how much time would you give me?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Ten minutes.

SHRI YADVENDRA DUTT: For a co-mover?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes. There can only be one mover.

SHRI YADVENDRA DUTT: I think the price of time has also risen with the prices.

Sir, the Prices have risen, but there is a certain pattern in the rise of prices. What prices have risen? That is the question. Please permit me to quote a few figures. The prices of the goods which are consumed by the common man, the poor man, have shot up Mustard oil—it is not consumed by the rich class at all. They go in for sudh ghee etc. and pay fantastic prices. The price of mustard oil has risen from Rs. 10/- to Rs. 11/- per Kg. About vegetables, I had a very strange and amusing experience at the Greater Kailash market. It has also been reported in the press because that thing was said before me and the press correspondent was also there. About onions, the Minister of Commerce said that onion export has been stopped and the price of onions will come down. Yet the prices are climbing and onions at times are not just available. May I quote the price of onions? The onions which were selling at 80 paise per Kg. are rarely available at Rs. 1.50 per Kg. The price has gone up by 200 per cent. When I asked the vegetable seller, he just said to me and I repeat it because the correspondent was there and he has published it in his report. The illiterate vendor has the audacity to ask: "why should we not increase the prices? After all we have somehow to get back the donations we paid to the party that was in power during the great Emergency"—i.e. to my friends opposite there. That is one part of it. I do not blame the vendor.

[Shri Yadavendra Dutt]

The rise in price is there in the case of onions, potatoes tomatoes and even sag During my childhood, if we bought vegetables for 2 annas, they would give spinach free of charge Lemons and something for the chutney also The price of spinach has doubled, i e from Re 1 to Rs 2 per kg This is an ordinary vegetable which was given away free during my childhood Now in the 30 years' rule of my friends —which they say, was a socialist rule—the position has come to this

अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा

Look at the pattern of this rise Let us take pulses Who consumes pulses ? I would not name anybody I know many of the socialist friends who are very rich--not rich in their own names, but in the names of their wives and nephews-- and they take excellent lunch at the Railway canteen Probably they don't take pulses But pulses are consumed by the ordinary common man, chaprasi, driver and the watchyand- ard people Look at the prices of pulses The price of moong dal was Rs 3 30 on 1st June it now costs Rs 4 50 per kg There are certain reasons for it also These pulses are sumggled outside I know from my personal experience-- and the matter was raised by me in the UP Assembly-- that at 3 points in the border our pulses were exported, by a friendly country, to Tibet A tin of kerosene oil which was selling here at Rs 16 or Rs 18 sold, in Tibet, at Rs 75 per tin It is our foodgrain which is feeding the Chinese Army in Tibet I would suggest to the government and repeatedly request them that they must take ruthless action on the borders of U P , Bihar and every other border from where this smuggling does take place

I was driving at the pattern of increase in price not affecting the rich man Take the case of chicken and eggs Chicken costs only Rs 11 And eggs cost Rs 4 a dozen There is no rise in the price of rich man's consumption Even in the case of cloth-- those gentlemen made a big hullaballo about the janata cloth It is not coming out any more What is coming out is the finest cloth at Rs.13, Rs 16 or Rs 18 per meter- There is no rise in the rich man's consumption Hardly there is a difference of 60 paise or 80 paise But in the poor man s consumption, there is a terrific rise Here is the pattern which is the result of the socio-economic structure that these gentlemen established, on which they claim credit from the country It is a fact of history Inflation is always a symptom of the socio-economic pattern of society Look at the Western countries They are suffering heavily due to inflation In America itself, which some of my friends laud, the inflation rate is in double digits This socio-economic structure has led to this inflation, and this inflation is the mirror of the entire socio-economic structure established by my friends This socio-economic structure has led to a certain pattern of consumption and production With the increased production of television, I am afraid none of the chaprasis or the rickshaw-wallas or taxi-wallas will be able to satisfy their hunger May be, my rich friends may be able to satisfy their hunger for luxury by the increase in the production of television sets, refrigerators or other luxury goods Now there is no increase in the cost of production of the high consumption elite pattern of society foodgrains But, so far as the essentials *of life are concerned, they claim a great* victory in exports.

पेट काट कर चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है ।

How to control this ? Government must make a two- pronged attack, immediate and long-range Immediate production means the ordinary goods of consumption must be produced heavily, especially in the agricultural sector How do you produce in the agricultural sector? I have great respect for Shri Mohan Dharia When I read his speech I was happy But when he answered my point on the edible oil, I was sorry for him Because, I put a very specific question to him You are claiming credit that 16 2 million tonnes of groundnut was produced Last year in the very same month there was a crisis in edible oil in Maharashtra They had that experience But, did they prepare a plan ? No Even after 30 years of shortage, there is no plan Shortfal in production is a ground After all, you have got 20 million tonnes of foodgrains Is it not a strange experience that you have 20 million tonnes of foodgrains in stock and yet the prices are going up ? People have not the money to buy. I am afraid the great plan has not yet come out to throw stock on the market to bring the prices down. I say learn from the past experience, build your plan for the future, take the future into view.

After all, increased agricultural production is essential and is a must in this country. There can be no two opinions about it How do you increase that ? Do you give the farmers an economic price? He is the only animal If I may use this word, who has no right to fix the price of his product in the world Every manufacturer fixes his own price of production, whether it is cloth, bidi or cigarette. But the poor farmer has no voice in fixing the price of his produce Previously, the price

was fixed by the middleman. Naturally, he kept his profit in view. Now the benevolent Government fixes the price, naturally keeping it as low as possible. After all he is also a producer. He is not a slave labourer or a second class citizen. But he is not fix his own cost of production.

That is why I say that there should be a Grain Board. By Grain Board I do not mean only a Wheat Grain Board. It should cover the entire gamut of agricultural produce. That Board should be autonomous. It should consist of bankers, agro-economists and Government representatives and of farmers who will put in their own point of view. That Board must take into consideration the cost of inputs, the rational profit which the farmer should get.

AN. HON. MEMBER : The majority of members should be farmers.

श्री यादवेन्द्र दत्त : डिटेन्स बाद में डिस्कस कर लेंगे।

The farmer should get his normal profit. The Board should announce the price long before the next crop comes into the market. If you are going to give the farmer an economic price, then there will be increase in production.

Secondly, you must give cheap inputs. We have been crying hoarse for fertilizers. In this country there are no big farmers, hardly two percent. Most of them are small farmers with one biswa, five biswa or one bigha of land, uneconomic holdings. If we are going to give fertilizer at Rs. 100 a bag, do you think he can ever make a profit ou tof it? He will be in a total loss. You must subsidise agricultural production. After all, the entire basis of life, of society, is food. The hon. Minister might see the European economic news of this morning and he will find that even a great country like Russia is suffering from a great deficit and has to buy food outside. So, this fundamental need must be met, and there must be a a strong public distribution system. It is not necessary to finish the trade part of it. Let the traders be there, but the public distribution system must be like an ankush on the elephant. It must be incorruptible, strong and and efficient.

In the short course, I would beg of the hon. Minister to take the harshest measures possible against big manufacturers and wholesalers because they are the hoarders. It is not the small people who are the hoarders at all. I tell you of my own experience. I was living with a relation before this Government gave me a house. During the emergency one of the dealers brought two trucks full of vanaspati and told my relation to take it to the Yamuna and throw the tins into it. You can imagine the number of tins. That is why I say it is the wholesale dealer and the big manufacturer who are the hoarders.

MR. DEPUTY- SPEAKER : Now that you have disclosed the fact, the police will be after him !

SHRI YADVENDRA DUTT: You may enquire from Mr. Bhinder !

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : He will be after the Member of Parliament !

SHRI YADVENDRA DUTT : The strongest possible measures must be taken. They must be put in prison. If you do not control prices, take it from me it will be the waterloo of the Janata Party. There will be no more Janata Party in this country. Empty stomachs are not going to make a fine distinction between democracy and illegality, as Mr. Samar Mukherjee will bear me out, as history will bear me out.

You have called conferences, You have made beautiful declarations, but the Cartesian and Platonic theories will not fill the stomach. Therefore, the harshest measures must be taken, and long-range, well-integrated, well-planned measures will have to be taken because life is a whole, not of parts, and you should change this pattern of production.

श्री ब्रज भूषण तिवाड़ी (खलीलाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष पेश किया है यह बहत ही सामयिक है क्योंकि आज देश में चीजो के दाम बढ़ने से स्थिति बड़ी भयानक बनती जा रही है। लोगों में इस कारण चिन्ता में

[श्री ब्रज भूषण तिवारी]

व्याप्त हो गई है और जनता सरकार भी इससे चिन्तित है। उसका प्रभाव या उसका दबाव आज इस सदन मे भी दिखाई दे रहा है। जिस जनता ने जनता सरकार को जिताया है उसकी बडी आकांक्षाऐं थी। जनतंत्र या जनता के मौलिक अधिकारो या उसकी आजादी पर जो संकट था खतरा था, वह तो दूर कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो हमारी आर्थिक स्थिति थी जो हमारे देश की अर्थ रचना थी और जिसके उस कारण देश रोगग्रस्त हो गया था उससे भी देश की जनता पीड़ित थी, त्रस्त थी और उसका भी निदान चाहती थी। जनता सरकार के आने पर हमने आजादी वाला मसला हल कर दिया लोकतंत्र को पुनर्जीवित कर दिया पुन स्थापित कर दिया। परन्तु जहा तक यह आर्थिक पहलू पर सरकार को कदम उठाने की या सरकार को कानून बनाने की बात है, वह भी हम कर रहे है और उस पर भी हम चल रहे है। परन्तु जिस हालत से हमको इस पर काबू पाना चाहिये वह नही पा रहे है। उसके कारण क्या है इस पर यह सदन भी विचार करेगा और अन्य माननीय सदस्यों ने उसके कारणों पर भी रोशनी डाली है। सरकार भी इस पर चिन्तित है, विचार कर रही है कि आखिर कारण क्या है। मै इस सदन के सामने केवल कुछ मौलिक बातो की तरफ ही ध्यान खींचना चाहूगा क्योकि आकडो मे हमारे सदस्यो ने यह साबित कर दिया कि जो आज यथा स्थिति है उसमे भी यह बात सही है कि चीजो के दाम बढे है। परन्तु इन चीजो के दाम केवल जनता सरकार के आने से या उसकी नीतियो के कारण बढ गये ऐसा मैं नही मानता इस मूल्य वृद्धि पर केवल जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक ढाचा इस देश म तैयार किया गया है उसी सदर्भ मे हमको विचार करना पडेगा। यह कारण है, रोग नही है। रोग कही और है। और अगर केवल कारण का निदान कर ले और रोग के कारणो की तरफ ध्यान न दे तो कोई नतीजा नही निकलेगा।

इस देश के अन्दर लगातार माग की गई कि दामो के बारे में कोई ठोस नीति होनी चाहिये। यह बात बराबर पिछली सरकार के सामने उठायी गई कि अपने देश मे जो आर्थिक अनुशासन है उसको कठोर किया जाय। लेकिन पिछली सरकार ने राजनीतिक अनुशासन लादने की कोशिश की, मगर जो कठोर आर्थिक अनुशासन लागू करना चाहिये था, जिन मर्यादाओ को अपने देश मे स्थापित करना चाहिये था वह नही लागू की गई। अभी माननीय कंवर लाल जी ने कहा कि यह जो मुनाफाखोरी है, जो दाम बढते है तो क्यो बढते है। यह सही है कि उत्पादन भी इसके लिये जिम्मेदार है उसका वितरण भी जिम्मेदार है। मगर उसके साथ ही साथ यह भी प्रमुख कारण है कि लोगो के अदर मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति अधिक है। यही सबसे बडा कारण है चीजो के दाम बढने का। और यह मुनाफे की प्रवृत्ति क्यो? भोग विलास की वजह से। एक तो जो आर्थिक जीवन मे अनिश्चयता का वातावरण है इस नाते लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर अपनी तिजोरी मे पूंजी संचित करना चाहते है। और दूसरी बात यह होती है कि लोग अपने मार्केट पर कब्जा करना चाहते है और जो भोग की सामग्री है उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो इस मुनाफे की प्रवृत्ति पर हम कैसे रोक लगायेंगे इसके लिये सरकार को कठोर कदम उठाने पडेगे। केवल उपदेशो से काम नही चलेगा, कठोर संकल्प और कठोर अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी। केवल हम प्रोफिट पर रोक लगा दे या सीलिंग लगा दे तो उससे काम नही चलेगा। मैंने कई बडे बड़े उद्योगपतियो मे व्यापारियो से बात की। वह कहते है कि इन्कम टैक्स जितना लगता है, 100 मैं मे 80 रु० टैक्स मे चला जाता है। तो क्यो मुनाफा कमायें, क्यों व्यापार करे। मगर इस टैक्स के अन्दर एक छूट है कि अगर हम उसका उपयोग करे तो उस पर रोक नही है, कोई पाबन्दी नही है। और उसका कारण

क्या है ? यहां पर सदन में कई बार चर्चा हुई कि जो बड़ी बड़ी फर्म और कम्पनियों हैं उनके डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स कितनी शान शौकत के साथ रहते है, कितना उनका खर्चा है, तनख्वाह है, भत्ता है, यह सब देख चुके है । और आज भी आंकड़े इस बात को साबित करेंगे कि जितना भोग का सामान है, फिजूलखर्ची के सामान हैं उनका उत्पादन बढ़ा है, और यह बात भी सदन के सामने आयी कि उनके दाम नही बढ़ रहे हैं। मगर जो आवश्यक चीजें हैं, जिससे गरीब आदमी की जिन्दगी पलती है, जो गरीब के लिये आवश्यक हैं उन्हीं चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे है । आखिर इसके सम्बन्ध में हमारी सरकार की क्या नीति हो, क्योंकि केवल मीसा से या कुछ केवल वक्ती पाबन्दी लगाकर यह तय करें तो यह तय नहीं हो पायेगा । मैं ऐसा मानता हूं कि इस सरकार, को, खासतौर पर मंत्री जी को विचार करना होगा कि कोनसा रास्ता हमको अख्त्यार करना है ? केवल प्राफिट पर ही पाबन्दी नहीं, खर्च पर भी पाबन्दी लगानी चाहिये तभी यह हो सकेगा । इस के साथ साथ ही अगर केवल खर्च पर ही पाबन्दी लगा दी तो कोई दूसरा रास्ता निकल आयेगा । इसलिये ऐसी चीजों के उत्पादन पर भी पाबन्दी लगानी चाहिये तभी इन्टोग्रेटेड एप्रोच होगी। मुनाफा, उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर पाबन्दी जब होगी तभी आप एक लक्ष्मण रेखा खींचेंगे । इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो कृषि उपज की चीजें है, उनके दाम बढ़ रहे हैं । यह सचाई नही है । जो खेती की चाजों के दाम बढ़ रहे है, यह कौन बढ़ा रहे हैं ? किसान अपनी फसल जब तैयार करता है और खेत से कटकर जब उसके खलिहान में आती है फिर वह घर पर जाती है । एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन में दाम कौन तय करता है ? जिसको फसल का ज्ञान नहीं, जिस ने खेत नहीं देखा, जिसने किसान की मुसीबत नहीं सही, जिसने उसकी कल्पना भी नहीं की वह लोग दाम तय करते हैं । और वह लोग केवल कागजी आंकड़ों पर और बड़े बड़े एयरकंडीशन्ड कमरों में बैठकर आंकड़ों के आधार पर, लागत के आधार पर चीजों के दाम तय करते हैं । मैं यह अर्ज करूंगा कि यह उचित नही है । दाम उनकी कास्ट और कारखानों की बनी चीजों की कीमत के सन्दर्भ में तय होने चाहिये ।

आज बिचौलिये लोग अनाज खरीद लेते हैं और खरीददार बड़े-बड़े शीत-गृहों में उसको स्टोर करते हैं । जब बाजार में चीजें उपलब्ध नहीं होती, और दाम चढ़ने लगते हैं, तब वह चीजें बेचते हैं । इन चीजों को रोकने के उपाय करने चाहियें । इससे किसान को कोई फायदा नहीं होता है । साथ ही साथ किसान की जो चीजें हैं, इनपुट्स हैं, और आवश्यक सामग्री है, वह मन्दी होनी चाहिये । इस पर विचार होना चाहिये और एक कठोर और न्यायपरक दाम नीति तय करनी चाहिये जो कि अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए ।

पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को ज्यादा फैलायें, दुकानों के सामने दाम की तख्तियां लगी हों और निश्चित कीमत हो । अगर कोई उनका उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये । मगर होता यह है कि बड़े कारखानेदार कानून के शिकंजे में नहीं आते हैं, होलेसेलडीलर कानून के शिकजे में नहीं आते, फुटकर व्यापारी ही कानून के शिकजे मे आते हैं । अगर फुटकर व्यापारी को डराकर ही मीसा या एमेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में बन्द करें तो उससे कोई विशेष काम नहीं ललेगा । सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि जो कारखानेदार हैं, बड़े-बड़े एजेन्टस् हैं, वह आपके पंजे में आयें । फार्वड ट्रेडिंग और सट्टाबाजारी को बन्द करना पड़ेगा । जनता सरकार ने इस तरफ भी कदम उठाये हैं । मैं चाहूंगा कि वह कदम सख्ती से उठाये । इसके लिये तात्कालिक कदम उठाने पड़ेंगे, दूसरे दीर्घकालिक और तीसरे अल्पकालिक कदम उठानें पड़ेंगे और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तारमुखी अर्थव्यवस्था बनाना पड़ेगा । यह संकुचित और रोगग्रस्त है, इसको रोग से

[श्री ब्रज भूषण तिवारी]

मुक्त करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर पायेंगे और चीजों के दामों की बढ़ोतरी को रोककर, सर्वसाधारण के जीवन को राहत पहुंचायेंगे और जीवन की चीजों को कम दाम पर सुलभ कर पायेंगे, जिसके लिये जनता पार्टी कृत संकल्प है ।

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) : It is now a stern reality that coming into power for nearly five months, the present Government has failed to curb the price rise. There are basic reasons; also there are immediate reasons. When we are discussing about the question of rise in prices, we should keep in mind that this problem is faced by the people in all capitalist countries; in no socialist countries, this problem is there. There is no question of price rise; there is no question of inflation in a socialist society.

So, the permanent solution of this problem only lies in the basic change of the entire society from capitalism to socialism. But that should be the real socialism, not simply the profession while the practice remains the same. So, our endeavour should be more and more social control on the means of production and on the means of distribution. If you do not take that direction in the economy, then we will be faced with more and more rise in prices, more unemployment, more corruption and more social tension and it is bound to intensify the people's agitation and there will be a final rupture in existing relations of production leading to a new one. This is the logical result of the capitalist system, Capitalism has some basic laws; these operate independent of the will and desire of the people

Now, we are in the midst of a capitalist system. Capitalism is based on the motive of profit. This is universal in every body's mind. So, to remove that motive from the exploiting classes, while capitalism remains intact, this is impossible. But . if the Government represents the real desire of the people, then for immediate measures, they will have to come forward with a sense of responsibility as well as with a fear for the future consequences in case of failure. Some stern measures, they will have to take keeping in mind that the entire society must be oriented towards more and more social ownership of the means of production and the means of distribution. So, more and more curbing of the monopoly and the profiters, that should be the direction. Without a direction, simply some immediate measures will not lead you to the desired results.

Unless you stabilise the prices, the whole economy is bound to go into doldrums, more rise in prices, more demand of the workers for wage increase, more bonus and there will be more and more agitation, and the argument will come there that the more you increase the wages the more you give the dearness allowance, the more you give bonus, there will be further inflation. That will have its chain effect on the economy and further price rise is inevitable. This is a vicious circle from which if you have to come out, You will have to keep in your mind the clear perspective that this system, entire social system must be changed basically. Otherwise there is no way out for all the 60 crore people to get rid of the life of sufferings through which they are passing. If you do not do that, there will be another revolution and this Government will be replaced by another Government; another government will come in its place. This is the law of the history; this is the law of social development. You cannot prevent that.

Two things Government should keep in mind. The first is that it is the moral duty of the Government of feed the people, supply the essentials of the people at a price which is easily within their reach and secondly, your Government is committed to this. You have given pledges before the elections that you will bring down prices, you will give relief to the people.....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We do not deny that.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : It is not a question of denying. People have experienced during the last five months. Whichever pledge you have given, is not being implemented. There is no conformation between your pledge and your practice. This was the way

the Congress had ruled for 30 years. For 30 years they nursed and built up capitalism, and capitalism has grown into monopoly capitalism. The monopolists are so powerful now that they have full control over the market. They have developed the holding power. Their power is so strong now that they can hold the essential goods from the market and artificially increase the prices. You cannot fight these big monopolists unless the entire Government comes with a determination and with the backing of the people. If you do not take the backing of the people, the people will go against you; only the monopolists will come to your rescue. That is the logic of history. But to give immediate relief to the people, my first emphasis is on the immediate perspective. I am leaving for the time being, the long-term perspective, that is, the socialist perspective. The immediate perspective should be that Government should take the entire responsibility for supplying foodgrains to the people. What is meant by 'entire responsibility'? That means, the essential commodities, particularly the foodgrains, should be taken out of the hands of the private traders. This demand we have repeated year after year, but the Congress Government did not pay any heed; we had even altercations with Mrs. Indira Gandhi. The entire foodgrain trade should be taken over in the hands of the Government; it should be taken out of the hands of private traders...

AN HON. MEMBER : Start from West Bengal.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : We will do if the Central Government comes to our help bacause our whole production is not sufficient for West Bengal.

This is the recommendation of the Planning Commission. The Planning Commission has always said that there should be some stability in prices, at least of the essential commodities; if the prices are not stable, it will have a chain reaction every where; the whole plan target will be completely offset. And that is what is happening. That is why, firmly, Government must undertake the responsibility for supplying foodgrains at cheaper prices to the people. That may be in the form of statutory rationing in places upto one lakh population and further increase in modified rationing. Not only foodgrains, but the other essential commodities also must be supplied under the public distribution system. But this distribution should be under the supervision of people's elected committees. There you get the involvement of the people. And if that is to be undertaken, procurement is very important, and Government should have direct procurement from the producers eliminating the middlemen. Then producers will get a fair price and the consumers also will get a fair price. The question has been posed here that, if the export of sugar for example, is stopped there will be accumulation of stock of sugar—and it was said that some 23 lakh tonnes of sugar were in the stock. Our suggestion is this. In the external market the price of sugar has come down. If you have to export sugar, you have to give subsidy. Our point is : give the subsidy for internal consumption. If subsidy is given for internal consumption, people get it at a cheaper price and the entire stock gets completely released. So, create demand among the people by giving subvention not for export but for *internal* consumption.

Similarly, you are thinking of exporting wheat. In the outside market, the price of wheat is much lower. So, if you have to export wheat outside, you will have to give subsidy, otherwise, the growers will be affected. So, here my point is this : give subsidy, for supplying wheat at a cheaper price to the consumers inside the country. You ask the State Governments for thus. They will get more stock for supplying through the public distribution centres. These policy changes will have immediate effect on the rise in prices and the prices will be checked. These are very important steps which Government should take.

Other aspects have been dealt with by friends. One is that the supply of liquid money should be controlled. It is a fact that banks are helping these business people and traders and, with the added strength of the banks aid they are holding the stocks and creating artificial want leading to price rise. That should be completely stopped. Government's control over the banks and its control over the essential commodities must be coordinated so that you can regulate the bank money for Government use to get sufficient stocks for the public distribution system.

श्री गेव एम० अवारी (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से मैं इस सदन में आया

[श्री गेब एम० अवारी]

हूं आज पहली बार एक ऐसा भाषण सुना जिससे मैं प्रभावित हुआ । श्री कंवरलाल गुप्त ने कोई भी पार्टीवाजी की बातें न करके टु काल स्पेड ए स्पेड—इस तरह का भाषण दिया । जो वास्तविक स्थिति थी उसको उन्होंने उसी तरह से रखा । मैं कंवरलाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज ठीक ठीक और अच्छी बातें हमारे सामने रखी ।

देश मे जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो उनका असर अधिकतर उन्ही व्यक्तियों पर पड़ता है जो मध्यमवर्गीय हैं । हम आप सभी रोज आकडे पढ़ते है और इस बात को जानते है कि इस देश के करीब करीब 75 फीसदी लोग बहुत बुरी तरह से गरीब है जिनको कि विलो पावर्टी लाइन कहा जाता है । इसलिए कीमतों का असर सबसे ज्यादा उन्ही लोगों पर पड़ता है ।

15.57 hrs.

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the chair*]

कंवरलाल जी ने अपने भाषण में साफ-साफ कहा है कि उन्ही वस्तुओं के दाम ज्यादा बढ़े है जिनको आवश्यक वस्तुयें कहा जाता है जैसे खाने के तेल, अनाज, साबुन, कपड़ा इत्यादि । जो वस्तुयें रोजमर्रा के लिए आवश्यक है उन्ही के दाम आज बहुत ज्यादा बढ़ गए है ।

मैं जानता हूं जब दाम बढ़ते है तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं । एक तो एकोनोमिक प्रिंसिपल्स की बात है । लेकिन आज हम एक बात नही भूल सकते कि आज के इस आधुनिक युग मे हमने बहुत सारी व्यवस्थायें देख ली है जैसे कैप्टेलिस्ट व्यवस्था और सोशलिस्ट व्यवस्था । लेकिन एक चीज आज हमारे सामने है जिसको कि गुप्त जी ने उठाया है और वह यह है कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उसके व्यापार पर कुछ न कुछ बंधन होना चाहिए । कुछ उसके प्राफिट पर भी बंधन होना चाहिए । इन आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में कुछ व्यापारी—सब नहीं—काला बाजारी करके भाव बढ़ाते हैं और प्राफिटियरिंग करते हैं । व्यापारियों का जो पुराना इतिहास है वह इसी प्रकार का रहा है । कभी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं और कभी वे आर्टिफिशल स्केयरसिटी पैदा कर देते हैं । राजा साहब ने अभी एक उदाहरण दिया कि तेल के डिब्बों को जानबूझ कर नदी में फेंक दिया गया ताकि स्केयरसिटी हो जाये और वे कीमतें बढ़ा सकें । ऐसी हालत मे मैं गुप्त जी से एक स्टेप और आगे जाकर कहूंगा कि जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण ही कर डाला जाये । केवल इन्ही चीजो का ही, अन्य चीजों का नही, ताकि इनके उत्पादन और वितरण की व्यवस्था पर सरकार ठीक ढंग से नजर रख सके । मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं बहुत से लोग कह देंगे कि राष्ट्रीयकरण होता है तो सरकारी अफसर बीच में आ जाते हैं और अफसरशाही से लोग नाराज होते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सरकारीकरण से ।

श्री गेब एम० अवारी : जैसा कामत साहब कह रहे है, ऐसा न हो कि इसका सरकारीकरण हो जाये लेकिन ऐसी व्यवस्था जरूर हो जिसके अन्तर्गत इसपर ठीक ढंग से प्रतिबंध लग सके और व्यापारी अनुचित फायदा जो उठाते हैं वह न उठा पायें ।

सभापति जी, आज के मोशन पर एक बहुत सुन्दर अमेंडमेन्ट श्री युवराज जी ने दिया है जिसमे उन्होंने कहा है कि एकदम जल्दी से जल्दी कामन मैन को रिलीफ मिलनी चाहिए । मैं जानता हूं—यदि हम ने राष्ट्रीयकरण का एक्सपेरिमेन्ट कर के देखा और उस के जो नतीजे निकलेंगे, उनको स्टडी किया गया

तो हम उस से भी एक स्टेप आगे जा सकते है। जैसा मैंने जनरल बजट के डिस्कशन के समय कहा था कि हमारे देश मे जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जिस पर सब तरह की मार पड़ती है, भाव की मार पड़ती है, टैक्सेशन की मार पडती है, हम उस मे एक मुद्दा यह भी ला सकते है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन को टैक्स फ्री किया जाय, यह एक तरह से उन के लिये इन्टेरिम-रिलीफ हो सकता है।

16·00 hrs.

श्री कंवरलाल गुप्ता के दो-तीन प्वाइन्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसा उन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्रीयकरण हो, तब तक प्राफिट पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, प्राफिट की सीमा बाधनी चाहिये। निष्पक्ष रूप से यदि पिछले पाच-छ सालो का अन्दाजा लगाया जाय, तो हम को इस बात को मानना पडेगा कि आर्थिक क्षेत्र मे पिछले वर्षों मे काफी कुछ फायदा हुआ है। मै इस बारे मे इस दृष्टिकोण से बोल रहा हू कि 1973 में जब सारे विश्व मे एक तरह का इन्फलेशन फैला हुआ था, बडे-बडे राष्ट्र उस के सामने झुक गये थे, उस समय भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाये, जिन से हम लोग बढती हुई कीमतो को कुछ हद तक रोक सके। इस की स्पष्टोक्ति हमारे कवरलाल गुप्त जी ने भी अपने भाषण मे दी है। इस प्रक्रिया को हमें आगे भी ले जाना चाहिये।

स्मगलर्स और प्राफिटीयर्स पर कडी से कडी कार्यवाही करने की बात उस समय भी चली थी और इसी लिये हमारे मोहन धारिया जी को आज यह कहना पडा कि यदि ट्रेडर्स उन की इस बात को नही मानेगे तो उन के खिलाफ मीसा के अन्तर्गत कदम उठाने पडेगे। यह बात उन्होंने इसी लिये कही कि जो व्यापार आज ट्रेडर्स के हाथ मे है, वे कर्तव्य को पहचाने, उन का हृदय परिवर्तन हो। लेकिन जो पैसा बनाने वाले लोग है वे इस तरह की बातो की परवाह नही करते, अपना फायदा उठाने चले जाते है। हमारे यहा स्मगलर्स के हृदय परिवर्तन की बात कही गई, इसी आधार पर उनको छोड दिया गया। लेकिन मैं पूछता हूं—क्या आप के पास कोई एक्सरे मशीन है, जिस से आप उन के हृदय को देख सकते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है या नही? ये लोग तो उगते हुए सूर्य को नमस्कार करते है, आप का सन्तोष करने के लिये बडी बडी बाते करेगे, लेकिन मौका आने पर फिर वही काम करेगे। इस लिये मै कहना चाहता हू—क्यो न ऐसी व्यवस्था हो कि जन-आवश्यक वस्तुओ का सीधा राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, उनके हाथ से यह व्यापार निकाल दिया जाय।

मै जानता हू—इस मे बहुत सारी तकलीफे है। हमारे यहा महाराष्ट्र मे "एकाधिकार कपास खरीदी योजना" (काटन मोनोपली प्रोकोरमेंट स्कीम) बनी, इस का सरकारीकरण हुआ लेकिन इस मे बहुत सी दिक्कते भी आई। लेकिन इस योजना के पीछे एक मूलभूत मुद्दा यह था कि इस व्यापार मे जो बडे-बडे पुराने व्यापारी थे, जो हजारो सालो से लूटते आ रहे थे उन पर नियन्त्रण लग सके। उनके हाथ से व्यापार को ले लिया जाय ताकि कीमतो को बढने से रोका जा सके। इस मे कुछ तकलीफे आई, इस लिये हमारी नई सरकार को उन तकलीफों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। हमारे श्री कंवर लाल गुप्त ने उन तकलीफो को दूर करने के लिये कुछ मूलभूत सुझाव दिये है। मैं समझता हूं कि उन के सुझावो को सरकार माने तो समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। उन के राष्ट्रीयकरण के सुझाव को माने—इस से काफी फायदा हो सकता है।

अन्त मे मै इतना ही कहूगा—यह सवाल पार्टीबाजी का सवाल नही है। मुझे दुख हुआ—जब कुछ माननीय सदस्यो ने यह कहना शुरु कर दिया कि एमर्जेन्सी मे यह किया गया, वह किया गया। यह एक फैशन बन गया है कि सब पार्टिया पूरा-का-पूरा उत्तरदायित्व एमर्जेन्सी पर ला कर थोप देती है। आज कई सैक्टर ऐसे है, जहा पार्टी-

[श्री गेव एम अवारी]

बाजो, मैरटेरियल-एटीच्यूड को छोड़कर काम करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीयकरण के काम को कोजिये, दूसरे अच्छे कामों को कीजिये, जिससे देश की जनता का भला हो। इकानामिक सैक्टर एक ऐसा सैक्टर है जहां पिछले दिनों मे काफी कुछ हुआ है, इस क्षेत्र को काफी वृद्धि हुई है, इसी तरह मे यदि हम इस क्षेत्र मे कुछ और काम करें तो यह हमारी ईमानदारी की प्रमाणिकता होगी।

मैं जानता हूं---जब हम लोग विद्यार्थी थे, हमारे मोहन धारिया जी, हमारे चन्द्र शेखर जो, जो हमारे युवा नेता थे, उन्होंने उस समय राष्ट्रीयकरण के मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठाया था। आज एक मत है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और दूसरा मत है कि राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि अब हमारे मोहन धारिया जी काफी मैच्योर हो चुके हैं---वे इस कार्य में आगे बढ़ेंगे और कोई सुन्दर योजना हम लोगों के सामने लायेंगे।

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, बोलने के लिए कितना समय मिलेगा ?

सभापति महोदय : 10 मिनट।

श्रीमती मृणाल गोरे : 10 मिनट में क्या बोल पाऊंगी, मुझे मालूम नहीं।

सभापति जी, सबसे पहली बात तो बिल्कुल साफ है कि इस देश में गये 30 सालों में जीवन-आवश्यक चीजों के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई, जितनी होनी चाहिये थी और आज महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि चीजें उपलब्ध नहीं है। कोई यह कहने की कोशिश करते हैं कि इसमें पार्टीबाजी का सवाल नहीं है और पहले जो कुछ हुआ है, उसमें हमे नहीं जाना चाहिये। आप मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि इसमें जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर पिछले 30 सालों में प्रोडक्शन, उत्पादन इस प्रकार बढ़ा देते कि जो जीवन-आवश्यक चीजें हैं उनकी उपलब्धि बढ़ जाती, तो फिर आज जो सवाल खड़ा हुआ है, वह खड़ा नहीं होता।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आबादी भी काफी बढ़ी है।

श्रीमती मृणाल गोरे : आबादी भी बढ़ी है लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नही बढ़ा है। जीवन-आवश्यक चीजों का जितना प्रोडक्शन बढ़ना चाहिये था, उतना नही बढ़ा। आप दालों, पलसेस को ही ले लीजिये। उनका उत्पादन कम हो गया है और इसलिए यह मुसीबत आ खड़ी हुई है। लांग-टर्मबेसिस पर हम विचार करें तो सही रूप मे अगर मूल्य-वृद्धि का कुछ इलाज करना है, तो यह बहुत ही आवश्यक है कि हमें उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिये। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिये, इन 10 मिनट मे मैं उन सब बातों में नहीं जा सकती लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कौन सी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसके बारे में हम लोगों को कुछ सोचना चाहिये जैसे खाद्य तेलों के बारे में मैं जानती हूं कि इसकी उपलब्धि इसलिये कम हो गई है क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन कम हो गया। यह बात सही है कि आबादी बढ़ी है लेकिन प्रोडक्शन भी कम हुई है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सभी फीगर्स यहां पर दूं लेकिन खाद्य तेल का पर-कैपिटा एवेलेबिलिटी जो 1976-77 में थी वह 4.9 किलोग्राम पर इयर है। इतनी एवेलेबिलिटी है जबकि यह कहा जाता है अच्छी स्वास्थ्य रखने के लिए कम से कम 21 किलोग्राम की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में एडिबिल आयल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप ने आज तक क्या किया है, यह मैं जरूर पूछना चाहूंगी। मूंगफली का उत्पादन

कम होता रहा । क्या आप ने कुछ किया उस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ? मध्य प्रदेश में करीबन डेढ़ लाख एकड़ जमीन ऐसी हैं, जहां सूर्यफूल का उत्पादन आसानी से हो सकता है । हम महाराष्ट्र की एसेम्बीली में लगातार तीन चार साल तक इस बात को उठाते रहे हैं कि इस का उत्पादन बढ़ाना चाहिए और सरकार यह कहती रही है कि हम सूर्यफूल का उत्पादन बढ़ाने का काम अपने हाथ में ले रहे हैं लेकिन असल में कुछ हुआ नही । यह बात बिल्कुल साफ़ है कि देश की आम जनता की जरूरत क्या है, यह देख कर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश नही हुई है और इसलिए मैं इस बात को जोर देकर कह रही हू । हमारे सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब यह कहेंगे कि उत्पादन बढ़ाने का काम हमारे विभाग के अन्तर्गत नही आता है लेकिन मैं यह कहूगी कि इस की तरफ ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है । जब तक आप इस को नही करेंगे, यह सवाल हल नही हो पाएगा । इसी प्रकार से मैं सब चीजों के बारे में फीगर्स दे सकती हूं कि उन की कितनी एवेलेबिलिटी है लेकिन अगर मैं सब फीगर्स देने लगी, तो और बातें कहने के लिए मेरे पास समय नहीं बचेगा । इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि एक तरफ़ तो प्रोडक्शन बढाने के लिए हमें क्या करना है, इस का पूरा इलाज हम करें और दूसरी तरफ मैं यह कहुंगी कि जो आज चीजों की उपलब्धि है, उस के वितरण की व्यवस्था ठीक तरह से होनी चाहिए, उस का बटवारा ठीक हो, इस के लिए भी कुछ करना चाहिए ।

बार-बार यह कहने में आता है कि आखिर बाजार में डिमांड एण्ड सप्लाई का नियम चलता है और इस के मुताबिक उपलब्धि कम है और मांग ज्यादा हैं, तो फिर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहने वाली है । यह तो कैपिटेलिस्टों की सी बात हो गई जिन के लिए ऐसे नियम बने थे लेकिन अगर हम दिल से चाहते हैं कि लोगों को ठीक दामों पर चीजें मिलें, तो जो भी चीजों की उपलब्धि है भले ही वह कम हो, उस का बंटवारा ठीक ढंग से होना चाहिए ताकि समाज के नीचे के तब्के के लोगों को कम से कम आवश्यक चीजें तो ठीक कीमत पर मिलें । यह बात बहुत ही आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यवस्था ठीक हो और जो चीजें जितनी उपलब्ध हैं, उन का वितरण ठीक ढंग से हो । मुझे खुशी है श्री धारिया जी ने पिछली सरकार ने जो कमेटी बनाई थी 1973 में खुद रिपोर्ट दी थी, वह इस कमेटी में थे और उस रिपोर्ट पर उस वक्त अमल नही किया जा सका था । लेकिन आज आपको मौका मिला है और आप उस रिपोर्ट को अमल में ला सकते है ।

आपको चाहिये कि आप वितरण की उचित व्यवस्था करें । जब किसी वस्तु की कमी हो तो उस वस्तु के उचित वितरण की व्यवस्था का होना बहुत जरूरी हो जाता है । इसमें उस कमी को भी आप पूरा कर सकते हैं ।

आपने एक निर्णय लिया है कि बहुत बड पैमाने पर जिन चीजों की देश को आवश्यकता है उनका निर्यात नही करेंगें । यह बहुत ही अच्छा निर्णय आपने लिया है । ऐसा करके आप उन चीजों की कीमतो को कम करने की कोशिश करते हैं । लेकिन बीच का जो दलाल वर्ग है वह आपकी कोशिशों को विफल करता जा रहा है । मैं मिसाल देती हूं । आपने कहा कि वैजीटेबल्ज की निर्यात नहीं होगी । इससे आपको आशा थी कि इनके दाम कम हो जाएंगे । बम्बई की बात मैं जानती हूं । कुछ दिन पहले मैं वहां गई थी । दिल्ली की सब मार्किट्स को मैं नहीं जानती हूं और न ही खुद जाती हूं खरीदने के लिए । इस वास्ते मुझे यहां का पता नहीं है । बम्बई का मुझे पूरा पता है । चार दिन पहले मैं वहां गई थी । मैंने पता किया तो पता चला कि जब आपका यह एनाउन्समेंट हुआ तो दो दिन के लिए जो सब्जी चार रुपए किलो थी उसके भाव ढाई रुपये किलो पर

[श्री मृणाल गोरे]

आ गए । लेकिन दो दिन के बाद फिर भाव पुराने आ गए, चार रुपये का भाव रिटेल मार्किट मे हो गया । उसके दो दिन के बाद पूना के जो सब्जी के उत्पादक थे, किसान, उनके प्रतिनिधि मुझे बम्बई मे आकर मिले और उन्होने मुझे बताया कि इस एनाउन्समेट के बाद दलाल जो सब्जी खरीदते थे उन्होने किसान के लिए तो भाव गिरा दिऐ लेकिन बाजार मे रिटेल मार्किट मे भाव नीचे नही लाए । इसका साफ अर्थ यह है कि दलालो ने अपना मुनाफा और भी बढा लिया और ग्राहक या किसान को कोई फायदा नही हुआ । बीच के इन दलालो को आपको खत्म करना होगा । आप कहते है कि ऐसा कोआपरेटिव मूवमेट को मजबूत करके ही किया जा सकता है । मुझे फिर कहना पडता है कि पिछले तीस साल मे सहकारी आन्दोलन को स्वाहाकारी आन्दोलन बना कर रख दिया गया है, जहा कही देखो सहकारी सोसाइटी मे खाने वाले लोगो की सख्या बढती गई है । इसलिए मै समझती हू कि इस तरफ भी आपको ध्यान देना होगा और दलाल का खत्म करने की जो कल्पना थी उस पर भी आपका विचार करना होगा ।

मन्त्री महोदय से मैं कहना चाहती हू कि हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा और बीच मे कोई भी अगर खाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर निगरानी करने का काम दक्षता—समितियो के द्वारा बिजिलेस कमेटीज के जरिये किया जाना चाहिये । इस काम म हमारा पूरा सहयोग रहेगा लेकिन आपकी तरफ मे भी हमे पूरा पूरा सहयोग मिलना चाहिये ।

जिन वस्तुओ की कमी है उनके वितरण की उचित व्यवस्था हो, इसकी आपको कोशिश करनी चाहिये ।

तेल के बारे मे मैं कुछ कहना चाहती हू । इसकी इस हाउस मे काफी चर्चा हुई है आपने इसका आयात भी करना शुरू कर दिया है । इसकी वजह से पिछले सप्ताह तक बीस तीस पैसे तेल के कम हो गए हैं, ज्यादा नही । यह मैं बम्बई की बात बता रही हूं । जो तेल आप आयात करते है उसमे पाम आयल भी है जो आज तक खाने के लिए वितरित नही होता था, दूसरे कामों के लिए उसका उपयोग होता था । अब मैंने सुना है कि प्रयोग चल रहे है कि इसको डबल रिफाइन करके और ब्लैड करके दूसरे आयल मे मिला कर इसको खाने लायक बनाया जाए । अगर ऐसा किया जाए तो मैं समझती हू कि इसको सात सवा सात रुपये के अन्दर बेचा जा सकता है । मैं तो यह कहूगी कि आप जितना पाम आयल एस० टी० सी० के जरिये इम्पोर्ट करते है, उसका सरकारी तौर पर पूरा इस्तेमाल कीजिये । साउथ मे जो कोकोनट आयल यूज करने है उसमे इसे ब्लैडिंग करके दीजिये । इसी प्रकार मध्य भारत मे मूगफली का तेल यूज होता है, नार्थ और ईस्ट मे मस्टर्ड आयल यूज होता है, तो आप सब मे इस आयल को ब्लैड करके दीजिये । तो जो लोग सस्ता चाहत है वह जरूर इस तरह का तेल लेने के लिये तैयार होगे । और इस तरह से कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल सकता है, वरना होता यह है कि जहा मस्टर्ड तेल चाहिये, वहा उसकी कमी पड जाती है, जहा मूगफली का तेल खाते है वहा आप रेपसीड आयल दे देते है तो लोग लेते नही है और फिर मृगफली के तेल की कमी पड जाती है । तो व्यावहारिक दृष्टि से लोगो की तुरन्त राहत पहुचाने के लिये आप इस प्रकार का रास्ता अपना सकते है, जिसकी बहुत जरूरत है ।

इसके अलावा व्यापारी होर्डिंग करते है जहा जरूरत है वहा पर उसे स्मगल आउट करने की कोशिश करते है । सीमा विभाग पर आज भी बहुत कोशिश इस तरह की चलती है । इसे बन्द करने के लिये आपको पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिये । मैं यह नही कहूगी कि मीसा का उपयोग करना चाहिये, मै इसके विरोध मे हू । किसी भी

हालत मे इसका उपयोग नही होना चाहिये। अगर एसेशियल कमोडिटीज एक्ट मे खामियां हैं तो उसे जरूर दूर कर दीजिये। हम सब आपके साथ है। आप चाहेंगे तो लोग सरकार के साथ रह कर सहकार करेंगे, लेकिन इसका तुरन्त इलाज होना चाहिये कि जो कोई भी होडिंग करता है, उसका पूरा इलाज होना चाहिये।

हम तो अखबारो मे पढते है कि बैंक वालो को कह दिया है कि ज्यादा क्रैडिट न दीजिये। लेकिन बम्बई मे दाई करोड रुपये का बैंक क्रैडिट मिला और 47 हजार बोरी दाल की रख दी। आज परिस्थिति ऐसी है। यह बात सही है या नही, इसका ही पता नही चलता है। हमारे ख्याल मे इसका पता आपको जरूर चल सकेगा आप पता लगाने की कोशिश कीजिये तभी इसका कुछ इलाज हो सकता है। हम तो अपने ढग से पता लगाते ही है लेकिन उसमे भी हमे आपकी मदद मिलेगी तो हम आगे कुछ काम कर सकते है।

आज जिन चीजो की कमी हम महसूस कर रहे है, उसका एक ही इलाज हो सकता है कि किसान से जिस कीमत पर यह चीजे ली जाती है, उस पर स्टोरेज और ट्रासपोर्ट चार्जेज लगा कर अगर आप ज्यादा से ज्यादा मनाफा लगाने की लिमिट तय कर दे और फिर उसके आधार पर वितरण की कीमत क्या होगी यह तय कर दे तो फिर डिमाण्ड और सप्लाई के ला पर कीमत तय नही होगी।

दूध की कीमत के बारे मे मैं कहना चाहती हू। इसकी कीमत कम करने की कोशिश के सिवाय देश मे आगे आने वाली पीढी के लिये हमने अपना फर्ज पूरा नही किया यह कल इतिहास मे लिखना पडेगा। तो इस दूध की कीमत को कैसे कम किया जाये, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इसके लिये आयल केक का एक्सपोर्ट बन्द करने के बारे मे हमें देखना होगा, उसके सिवाय दूध की कीमत कम नही होगी। आज दिल्ली मे 62 पैसे की आधे लिटर की दूध की बोतल मिलती है, जबकि बम्बई मे एक रुपये 30 पैसे की आधे लिटर की बोतल मिलती है। इतनी महगी बोतल लेकर कोई भी बच्चो को घर मे दूध नही दे सकता है, चाय के सिवाय और कुछ नही हो सकता है।

इसके अलावा ड्रग्ज के बारे मे मैं कहना चाहती हू। पैट्रोलियम और कैमिकल्स की मिनिस्ट्री की डिमाड्ज पर बोलते हुए मैंने कहा था कि नेशनल ड्रग अथौरिटी या कुछ ऐसी ही अथौरिटी बना कर जो जीवन के लिये आवश्यक और जरूरी दवाइयां हैं, उनकी कीमत कैसे कम हो, यह देखा जाना चाहिये। जितने फार्मेस्युटिकल वर्क्स हैं उनके आफिस, एडवर्टाइजमेंट का खर्च, लान्स, बगीचे, बिल्डिंग यह सब चीजे अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ड्रग्ज की कीमते क्यो इतनी बढ जाती है।

हम लोगो को देखना चाहिए कि जीवनावश्यक ड्रग्ज की कीमतें कैसे कम हो। मेरे ख्याल से वे जरूर कम हो सकती है। लेकिन अगर हम पिम्परी की सरकारी पैन्सिलिन फैक्टरी मे बनाई गई ड्रग्ज की कीमते बढा देंगे, तो फिर हम प्राईवेट कम्पनीज को क्या कहेंगे?

जहा तक कपडे का सम्बन्ध है, गरीब वर्ग आज बहुत ही मुसीबत मे है—वह कपडा नही खरीद सकता है। आज एक सवाल के उत्तर मे बताया गया है कि जनता कपडे के नाम से जो सस्ता कपडा बेचा जाता है, उसके बारे मे कोई शिकायत नही है। मैं तो इतना जानती हू कि कीमत के हिसाब से वह कपडा बिल्कुल पहनने लायक नही है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पहले जमाने मे कपडे पर एक्स-मिल प्राइस, एक्साइज ड्यूटी और रिटेल प्राइस लिखी जाती थी। लेकिन अब कीमत के बारे मे केवल यह लिख

[श्री मृणाल गोरे]

दिया जाता है कि "नाट मोर देन—"। हमने देखा है कि मिल की प्राइस से सौ फी सदी से भी ज्यादा फ़ायदा कर के वह कीमत लिखी जाती है। उसमें बहुत मुनाफ़ाखोरी चलती है। अगर कपड़े की कीमत तय करने के बारे में पहले के तरीके को अपनाया जाये, तो कपड़े की कीमत कम करने में कुछ मदद मिल सकती है।

इनफ्लेशन और डेफ़िसिट फ़िनांसिंग को कम करने आदि लांग-टर्म स्टेप्स पर हमें विचार करना चाहिए। इस देश में पिछले तीस सालों में ऊपर से लेकर नीचे तक फ़िजूलख़र्ची बहुत बढ़ गई है। हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा जी सादगी की बात कहा करते थे। हम सादगी की बात तो बहुत करते रहे हैं, लेकिन इस देश में फ़िजूलख़र्ची बढ़ती चली गई है। पाछे के दरवाजे से, बैकडोर से, जो पैसा आता रहा, उसके कारण फिजूलख़र्ची बढ़ती रही। इसे कम किये बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। उसके बिना हम इनफ्लेशन भी कम नहीं कर पायेंगे।

जहां इनफ्लेशन कम करना और प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है, वहां लोगों में यह विश्वास होना चाहिए कि हमें न्याय मिलने वाला है, क्योंकि तभी वास्तविक उत्पादकों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे समाज के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करें।

मैं जानती हूं कि यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जो काम तीस साल में नहीं हुआ है, उसे करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सरकार कीमतों के बारे में कुछ ठोस कदम उठायेगी।

PROF. R. K. AMIN (Surendranagar) : Mr. Chairman, Sir, in my view a good deal of confusion prevails on this issue both in regard to its diagnosis and its prescriptions. My hon. friend opposite when he was describing the causes leading to the present situation for the price rise referred to inflation, speculation and hoarding but when t he rescription was suggested he himself said that merchants are not to be punished.

When my friend, mover of the resolution, was describing the various measures to be taken, *e.g.* appointment of a Committee for the essential commodities, giving more powers to the Police, organising or increasing the distribution agencies and what not even he suggested to the arrest of the Oil importers, I feel that he has dealt with the symptoms but not with the substance. (*Interruptions*) If I look to the Government also, I do not get the correct diagonosis. The hon. Finance Minister, in his speech, described that the supply of the money is the villain of the piece. If I go to the Economic Survey, it describes the supply of money as well as the shortage of a few commodities as main causes and if I go to the hon. Minister, Mr. Mohan Dharia, he will suggest that the mismanagement of the supply position of certain commodities along with the supply of money, is the main reason for landing us into this difficulty. That is why I suggest that this problem should be viewed in its proper perspective. It is only then that a correct diagnosis can be given and we can also have a proper prescription.

Now we should know that and we should not stress this problem disproportionately. It is true that during the last year, say from March 1976 to March 1977, the rise in price was 12% and since then it has been rising at the rate of 2% per month. But it does not mean that we will multiply it by 12 and say that the inflation is recurring at the rate of 24% during a year. It may be a temporary phenomenon. There are good rains and the monsoon is good. Probably after Diwali or during October-November, we might have a very good crop. Why I tell you this ? I know the oil prices or the groundnut prices which are prevailing in the market are very high. But in Rajkot, even today you will find that there are people who are giving assurance that they would supply groundnut oil at Rs. 70.00 per tin in the month of November. They expect that the rains will be good and in the month of November there will be a good supply of groundnut oil and they will be able to supply the oil at Rs. 70.00 per tin. This is how selling and purchasing are taking place at Rajkot in regard to the groundnut oil. Therefore, it is not necessary to multiply it by 12 and say that the inflation rate is 24% during this year. We must also realise that once the supply of money increases, the rise in price does not take place immediately. It has a delayed effect. The rise in money supply might have taken place last year, but the effect on the prices might come after 3 months in some commodities, and after six months in some other commodities. So, the rise in price may be due to increase in the supply of money which had taken place during the last year. This is the delayed action. We should also realise that in many of the commodities the price rise during this year is very high.

It is so in oil seeds, oil and also in pulses. These are the commodities which are having the seasonal production, which cannot be dealt with now because substitutes are not available.

MR. CHAIRMAN: Prof. Amin, you can continue tomorrow.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, I want to know whether it will be taken up tomorrow.

SHRI MOHAN DHARIA: Sir, I will have to see when it will be included in the agenda. I am sure tomorrow it will not be included in the agenda.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Why not tomorrow ?

MR. CHAIRMAN: We do not know what will be the tomorrow's agenda.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Four hours are allotted for this purpose. Two hours are over and two hours are still there. Let us take the consensus of the House.

MR. CHAIRMAN: I understand that tomorrow's agenda has already been announced. But anyhow it will be taken up.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : For instance, yesterday the censure motion was not over and it was taken up today, though there was no censure motion scheduled for today. Similarly, we can have a discussion for two hours tomorrow. Let us take the opinion of the House.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar) : Four hours had been allotted; two hours had been utilised and two hours remain. My point is that two hours must be found either tomorrow or on Monday, within this session; it cannot be indefinite; this resolution cannot go on to the next session. By that time prices may rise further.

MR. CHAIRMAN : Your suggestions will be considered by the hon. Speaker.

SHRI MOHAN DHARIA : Tomorrow there is the discussion on the reports of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; let us not disturb that discussion. This should be taken up on Monday; this should be conveyed to the hon. Speaker.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The White Paper has to be discussed on Monday. I am really sorry.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : We can sit till midnight.

MR. CHAIRMAN : You are encroaching on Mr. P.K. Deo's time now. Your suggestions will be considered by the hon. Speaker and he will take a decision.

PROF. P. G. MAVALANKAR : Leaving everything to Monday would bring us difficulties; Monday is already full. Tomorrow we can sit longer, after that other debate is over.

SHRI MOHAN DHARIA : Tomorrow after that debate is over, we can sit. Please take it up with the Speaker.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Tomorrow after the discussion on Scheduled Castes and Tribes is over at 6 p.m. or 7 p. m. we can take this up. That is the decision of the House.

MR. CHAIRMAN : I shall convey it.

16.32 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Fifth Report

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : I beg to move :

"That this House do agree with the Fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 3rd August 1977."

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore) : Before you put this motion to the vote of the House, may I make a submission ? There are three Bills categorised as A. During this session I think 8 Bills have been categorised as A. My suggestion is that if the Private Members' Bills and Resolutions Committee gives category A to almost all the important Bills, then perhaps there is no meaning in balloting because in the ballot those bills which get priority will push them back ; they will never come up for discussion. Therefore, I should like to convey to the committee that it should be more discreet in giving 'A' category to the Bills in future.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That this House do agreee with the Fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 3rd August, 1977."

The motion was adopted.